



एयर इंडिया विनिवेश

drishtias.com/hindi/printpdf/air-india-disinvestment

पिरलिम्स के लिये:

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग

मेन्स के लिये:

रणनीतिक निवेश की आवश्यकता, महत्त्व और चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने 'एयर इंडिया' (AI) में भारत सरकार की शत-प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी की बिक्री (विनिवेश) के लिये 'टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड' की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'टैलेस प्राइवेट लिमिटेड' की सबसे उच्चतम मूल्य बोली को मंजूरी दे दी है।

'एयर इंडिया' में टाटा की 100% हिस्सेदारी होगी, साथ ही इसकी अंतर्राष्ट्रीय शाखा- एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100% और ग्राउंड हैंडलिंग संयुक्त उद्यम- 'AI SATS' में 50% की हिस्सेदारी होगी।

Tata in the sky | Tata Sons will be the new owner of debt-laden national carrier Air India. The sale marks the return of Air India to the Tata group, a pioneer in aviation

1932: JRD Tata pilots Tata Airlines' inaugural flight from Karachi to Bombay	2007: Air India merges with Indian Airlines, that operates only domestic routes	Jan, 2020: Govt. launches a second attempt, this time offers 100% stake in Air India
1946: Tata Airlines becomes a public company; renamed Air India Limited	2012: Govt. approves ₹30,000 crore bailout for Air India, which has over ₹67,000 crore in debt	Oct, 2020: Govt. confirms Tata Sons' subsidiary Talace Pvt. Ltd. as the winning bidder
1948: Govt. of India acquires a 49% stake in the carrier	May, 2018: Govt. attempts to sell 76% stake in Air India; attracts no bidders	
1953: Government nationalises Air India		



प्रमुख बिंदु

• विनिवेश का कारण

- यह आशा की जाती है कि 'एयर इंडिया' के निजीकरण से इसके संचालन एवं लागत को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा, साथ ही इससे यात्रियों के लिये सेवाओं में सुधार होगा और वाई-फाई जैसी बुनियादी सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
- भारत में एक मज़बूत अंतर्राष्ट्रीय वाहक के रूप में एयर इंडिया दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और बंगलूरु में निर्मित बड़े हवाई अड्डों को बढ़ावा देगी, साथ ही इसके माध्यम से एयर इंडिया विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकेगी।
- एयर इंडिया के सफल बदलाव से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मदद मिल सकती है क्योंकि यह एक अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि विमानन का अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ता है।
- सरकार पर आर्थिक सुधार का समर्थन करने और स्वास्थ्य देखभाल हेतु उच्च परिव्यय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये संसाधन जुटाने का दबाव है।

• महत्त्व

- यह एयर इंडिया के दैनिक नुकसान के भुगतान में खर्च होने वाले करदाताओं के पैसे को बचाएगा।
- यह उन अन्य कठोर निर्णयों को लेने मदद करेगा, जिनके लिये सरकार इच्छुक है।
- यह संभवतः घरेलू स्तर पर एक और कम लागत वाले वाहक का विकल्प प्रदान करेगा।

विनिवेश

- सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन, आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, परियोजनाएँ या अन्य अचल संपत्ति को विनिवेश कहा जाता है।
- सरकार राजकोषीय बोझ को कम करने या अन्य नियमित स्रोतों से राजस्व की कमी को पूरा करने जैसे विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये धन जुटाने हेतु विनिवेश करती है।
- **रणनीतिक विनिवेश** एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण का किसी अन्य इकाई (ज्यादातर निजी क्षेत्र की इकाई) को हस्तांतरण है।
- साधारण विनिवेश के विपरीत रणनीतिक बिक्री का तात्पर्य एक प्रकार का निजीकरण है।
- वित्त मंत्रालय के तहत **निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM)**, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के लिये नोडल विभाग है।
- भारत में रणनीतिक विनिवेश को बुनियादी आर्थिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाता है ताकि सरकार उन क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण/उत्पादन में खुद को संलग्न न करे जहाँ प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार की स्थिति हो।
- विभिन्न कारकों जैसे- **पूँजी का संचार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कुशल प्रबंधन प्रथाओं** आदि के चलते रणनीतिक निवेशकों के माध्यम से ऐसी संस्थाओं की आर्थिक क्षमता को बेहतर किया जा सकता है।

DIFFERENT APPROACHES TO DISINVESTMENT

- Minority Disinvestment: A minority disinvestment is one such that, at the end of it, the government retains a majority stake in the company, typically greater than 51%, thus ensuring management control.
- Majority Disinvestment: A majority disinvestment is one in which the government, post disinvestment, retains a minority stake in the company i.e. it sells off a majority stake.
- Complete Privatisation: Complete privatisation is a form of majority disinvestment wherein 100% control of the company is passed on to a buyer.

स्रोत: पीआईबी
